

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2022 का आपराधिक आवेदन (खण्डपीठ) संख्या 357

थाना काण्ड संख्या -385 वर्ष-2014 थाना-तिलौथू जिला-रोहतास से उत्पन्न मामला ।

मो. महमूद आलम, पिता- स्वर्गीय माजिद साबरी, निवासी गाँव-तिलौथू, थाना.-
तिलौथू, जिला-रोहतास

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/गण

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए : श्री मो. अताउल हक, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री अभिमन्यु शर्मा, एपीपी

भारतीय दंड संहिता---धारा 365, 366 (ए), 376---पोक्सो अधिनियम, 2012---
धारा 2 (डी), 5, 6, 29, 30, 34 (2)---किशोर न्याय अधिनियम, 2015---धारा
94--पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़िता की आयु का निर्धारण---सजा के खिलाफ
अपील---अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उसने पीड़िता, एक नाबालिग लड़की
को नशीला पदार्थ देकर बलात्कार किया है।

निष्कर्ष: - कानूनी आवश्यकता के बावजूद, अभियोजन पक्ष ने पीड़िता की आयु के
संबंध में कोई स्कूल प्रमाण पत्र या पंचायत या नगरपालिका प्राधिकरण प्रमाण पत्र
रिकॉर्ड पर नहीं लाया है --- पीड़िता के पिता की मौखिक गवाही और चिकित्सा
राय के मद्देनजर, पीड़िता कथित घटना की तारीख को 12 वर्ष से अधिक उम्र की
पाई गई और, इसलिए, पीड़िता एक बच्ची थी और पोक्सो अधिनियम के प्रावधान
अपीलकर्ता के खिलाफ लागू होते हैं --- यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि
अभियोक्ता की एकमात्र गवाही के आधार पर, आरोपी को उसकी गवाही की पुष्टि के
बिना दोषी ठहराया जा सकता है, बशर्ते उसकी गवाही विश्वसनीय हो और अदालत
का विश्वास जगाने वाली हो --- अभियोक्ता (पी.डब्लू-5) की गवाही सुसंगत, सत्य
और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित है, जिसके अनुसार पीड़िता की योनिद्वार की
झिल्ली टूटी हुई पाई गई थी और पी.डब्लू-6 जिसने उसकी जांच की है, ने राय दी
है कि बलात्कार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है --- छोटी-छोटी
बातों पर कुछ मामूली विसंगतियों के बावजूद उसके बयानों में कोई बड़ा

विरोधाभास नहीं है जो अभियोजन पक्ष के मामले और उसके समग्र तथ्य की जड़ तक जाता है गवाही सच्ची और विश्वसनीय है--- इसलिए, अपीलकर्ता पीड़िता के विरुद्ध प्रवेशात्मक यौन हमला करने का दोषी है - हालांकि, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दोषी/अपीलकर्ता को POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत सजा सुनाकर गलत वैधानिक प्रावधानों को लागू किया है क्योंकि पीड़िता की आयु 12 वर्ष से अधिक पाई गई है और इसलिए, उसके विरुद्ध किया गया प्रवेशात्मक यौन हमला, POCSO अधिनियम की धारा 5 के तहत परिभाषित गंभीर प्रवेशात्मक यौन हमले के अंतर्गत नहीं आता है - सजा को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कठोर कारावास से घटाकर 10 वर्ष कारावास कर दिया गया - अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। (पैरा 47, 52-58)

पोक्सो अधिनियम---पीड़ित की आयु का निर्धारण---प्रक्रिया----पोक्सो अधिनियम के लागू होने के लिए एक शर्त यह है कि क्या अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है कि कथित पीड़ित घटना के दिन बच्चा था, यानी 18 वर्ष से कम आयु का था---विधि से संघर्षरत किशोर की आयु के निर्धारण के लिए प्रदान की गई प्रक्रिया को अपराध के पीड़ित की आयु के निर्धारण के लिए भी अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि जहां तक अल्पसंख्यक के मुद्दे का संबंध है, विधि से संघर्षरत बच्चे और अपराध के पीड़ित बच्चे के बीच शायद ही कोई अंतर होता है---ऐसे में पीड़ित की आयु का निर्धारण स्कूल से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र या पंचायत या नगर प्राधिकरण प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो, के आधार पर किया जाता है---उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में पीड़ित की आयु का निर्धारण अस्थिभंग परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा परीक्षण द्वारा किया जाना आवश्यक है---कानून की यह स्थापित स्थिति है कि किसी व्यक्ति की आयु के बारे में चिकित्सा राय निर्णायक साक्ष्य नहीं है, क्योंकि आयु का सटीक आकलन चिकित्सा परीक्षण के आधार पर नहीं किया जा सकता है क्योंकि उच्च और निम्न दोनों पक्षों में त्रुटियों की संभावना हमेशा बनी रहती है---हालांकि, जे.जे. अधिनियम की धारा 94 (2) में उल्लिखित दस्तावेजों की अनुपस्थिति में मेडिकल राय बहुत उपयोगी मार्गदर्शक कारक हो सकती है। (पैरा 37, 41, 45)

(2013) 7 एससीसी 263, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 846, (2022) 8 एससीसी 602, (2017) 2 एससीसी 210, (2015) 7 एससीसी 773, (2012) 10 एससीसी 489पर भरोसा किया गया।

1988 एसयूपीपी एससीसी 241, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1358, (2017) 11 एससीसी 195, (2012) 4 एससीसी 79, 2009 (1) जेआईजे 1, एआईआर 2009 एससी 152, (2008) 16 एससीसी 73, (2007) 14 एससीसी 150, (2006) 4 एससीसी 512, (2006) 11 एससीसी 444, (2005) 9 एससीसी 195, (1981) 3 एससीसी 675, (1977) 4 एससीसी 452, (2010) 9 एससीसी 567, एआईआर 2010 एससी 3071, एआईआर 1988 एससी 696, 1973 एआईआर 2622, 2019 एससीसी ऑनलाइन पैट 1077, (2013) 14 एससीसी 159, 2018 (4) पीएलजेआर 160, 2013 (10) स्केल 454, (1999) 9 एससीसी 525, (2017) 11 एससीसी 195 संदर्भित।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार
और
माननीय श्री न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार
सीएवी जजमेंट
(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)
तारीख: 30-10-2024

वर्तमान अपील, तिलौथू पी.एस. केस संख्या 385/2014 से उत्पन्न POCSO केस संख्या 25/2015 में विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-VII,- सह-अनन्य विशेष न्यायालय (POCSO) अधिनियम, सासाराम, रोहतास द्वारा क्रमशः दिनांक 25.03.2022 और 29.03.2022 को पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले के खिलाफ पेश की गई है, जिसके तहत एकमात्र अपीलकर्ता को धारा 376 I.P.C तथा पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 5/6 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है। हालांकि, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत सजा नहीं सुनाई गई है, बल्कि उसे पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है तथा 50,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई है। पीड़िता

को पुनर्वास के लिए 4,00,000/- रुपये का मुआवजा भी दिया गया है, जिसका भुगतान सासाराम में डीएलएसए रोहतास द्वारा किया जाएगा।

अभियोजन मामला।

2. तिलौथु पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को 6.5.2014 पर दी गई सूचना देने वाले की लिखित रिपोर्ट से अभियोजन पक्ष का मामला सामने आया है कि 04.05.2014 पर, उसकी 10 साल की भतीजी को अपीलकर्ता, जो उसका सहायक है, अपनी बेटी की सेवा करने के बहाने बनारस ले गया था, जो एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी। बनारस में, उसकी भतीजी के साथ मादक पदार्थ पिलाने के बाद अपीलार्थी द्वारा बलात्कार किया गया था। जब वह 6.5.2014 पर उसके साथ घर आई, तो उसने उसे घटना के बारे में बताया।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि।

3. लिखित रिपोर्ट के आधार पर, दिनांक 06.05.2014 को 23 बजे एकमात्र आरोपी मोहम्मद महमूद आलम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के बाद, अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 365, 366 (ए) और 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दिनांक 22.06.2014 को आरोप पत्र संख्या 29/2014 प्रस्तुत किया गया। अपीलकर्ता के खिलाफ विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 11.07.2014 को अपराध का संज्ञान लेने के बाद, मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 365, 366 (ए) और 376 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप तय किए गए और उन्हें आरोपी को पढ़कर सुनाया गया तथा समझाया गया, जिस पर उसने खुद को निर्दोष बताया तथा मुकदमा चलाने का दावा किया। इसलिए, मुकदमा शुरू हुआ।

4. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित दस गवाहों से पूछताछ की गई:

(i) पीडब्लू 1:- पीड़ित की माँ

(ii) पीडब्लू 2:- पीड़ित की दादी

(iii) पी. डब्ल्यू. 3:- पीड़ित/मुखबिर के चाचा।

(iv) पीडब्लू 4:- पीड़ित के पिता।

(v) पीडब्लू 5:- पीड़ित।

(vi) पीडब्लू 6:- डॉ. ऋचा चौधरी

(vii) पीडब्लू 7:-डॉ. पीयूष कुमार पुष्कर

(viii) पीडब्लू 8:- अभिनंदन कुमार सिंह

(ix) पी. डब्ल्यू. 9:- डॉ. विजय कुमार सिंह

(x) पीडब्लू 10:- धीरेंद्र यादव

5. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी दर्ज किए:

(i) प्रदर्श 1:- फरदबेयान पर सूचना देने वाले का हस्ताक्षर

(ii) प्रदर्श 2:- पीड़ित की धारा 164 Cr.PC के तहत बयान पर हस्ताक्षर

(iii) प्रदर्श 3:- चिकित्सा रिपोर्ट

(iv) प्रदर्श 4:- चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट

(v) प्रदर्श 4/1:- मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर डॉ. विजय कुमार सिंह के हस्ताक्षर।

धारा 313 Cr.PC के तहत वक्तव्य

6. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के बाद, अभियुक्त से धारा 313 सीआरपीसी के तहत पूछताछ की गई, जिसमें उसे अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में आने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, ताकि उसे उन परिस्थितियों को समझाने का अवसर मिल सके। इस जाँच के दौरान, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने खिलाफ अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य सुने थे। लेकिन उन्होंने किसी भी परिस्थिति की व्याख्या नहीं की, हालांकि उन्होंने दावा किया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य झूठे हैं और वह निर्दोष हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की शादी दूसरी लड़की से कराई थी।

7. अपीलार्थी ने अपने बचाव में निम्नलिखित तीन गवाहों से भी पूछताछ की है:

(i) डी. डब्ल्यू. 1- शाहबुबन बीबी

(ii) डी. डब्ल्यू. 2- नजरून खातून

(iii) डी. डब्ल्यू. 3- साइबुन निशा

विचारण न्यायालय के निष्कर्ष।

8. विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करने और पक्षों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, दोषसिद्धि और सजा के आदेश का विवादित निर्णय पारित किया, जिसके तहत एकमात्र अपीलार्थी को दोषी पाया गया और तदनुसार सजा सुनाई गई।

पक्षों की प्रस्तुतियाँ।

9. हमने अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील और राज्य के लिए विद्वान एपीपी को सुना है।

10. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का विवादित निर्णय और सजा का आदेश कानून की नजर में या तथ्यों के आधार पर टिकने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपना न्यायिक विवेक नहीं लगाया है और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन करने में विफल रहा है, जिसके कारण गलत विवादित निर्णय और आदेश पारित हुआ है।

11. गैर-सरकारी अभियोजन पक्ष के गवाह अभियोक्ता या उसके करीबी परिवार के सदस्य जैसे पिता, माता, चाचा और दादी हैं और इसलिए, वे भरोसेमंद और विश्वसनीय नहीं हैं। उनकी गवाही अपीलकर्ता की सजा का आधार नहीं हो सकती।

12. उन्होंने आगे कहा है कि अभियोजक (पी.डब्ल्यू-5) केवल चश्मदीद गवाह है और वह विश्वसनीय या भरोसेमंद गवाह नहीं है, क्योंकि उसकी गवाही प्रमुख विसंगतियाँ और विरोधाभास से भरी हुई है।

13. उन्होंने आगे कहा है कि विद्वत निचली अदालत ने दोषसिद्धि और सजा के लिए पॉक्सो अधिनियम के गलत वैधानिक प्रावधानों को लागू करके कानून की गंभीर त्रुटि की है। उन्होंने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत ऐसी कोई सजा नहीं दी गई थी जो वर्ष 2019 में इसके संशोधन से पहले मौजूद थी। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पॉक्सो अधिनियम की अधिक से अधिक धारा 4 और आई.

पी. सी. की धारा 376 (1) लागू होगी। कथित घटना के समय मौजूद धारा 4 के अनुसार केवल 7 साल के लिए न्यूनतम कारावास का प्रावधान है, हालांकि सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

14. हालांकि, राज्य के लिए विद्वान ए. पी. पी. ने दोषसिद्धि के विवादित फैसले और सजा के आदेश का बचाव किया और प्रस्तुत किया कि विवादित फैसले में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है और अपीलार्थी को उचित रूप से सजा सुनाई गई है।

15. हमने अभिलेख पर प्रासंगिक सामग्री का पूरी तरह से अध्ययन किया है और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार किया है।

पॉक्सो अधिनियम के आवेदन के लिए पीड़ित को अल्पसंख्यक साबित करने के लिए अभियोजन की आवश्यकता।

16. पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अपराधों से संबंधित है 30-10-2024 जैसा कि अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट है कि बच्चों के खिलाफ किया गया है, और अधिनियम की धारा 2 (डी) के अनुसार, बच्चे का अर्थ है 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। इसलिए, पॉक्सो अधिनियम के आवेदन के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि कथित पीड़ित घटना की तारीख को 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा था और यह अभियोजन पक्ष है जो आरोपी/अपीलार्थी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के आवेदन के लिए पीड़ित के अल्पसंख्यक को साबित करने की आवश्यकता है।

पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 29 और 30 के तहत अनुमान लगाने के लिए कथित अपराध के मूलभूत तथ्यों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की आवश्यकता।

17. यह भी कानून की स्थिति है कि कथित अपराध के मूलभूत तथ्यों को भी अभियोजन पक्ष द्वारा साबित करने की आवश्यकता है, अदालत के समक्ष आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और 30 के तहत अनुमान लगाया जाता है। एफ. आई. आर. जमा करने या पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप पत्र जमा करने से मुकदमे के दौरान आरोपी के अपराध का अनुमान स्वचालित रूप से नहीं लगता है। अभियुक्त के निर्दोष होने का अनुमान हमारे

संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में निहित हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत है।

18. बाबू बनाम केरल राज्य, (2010) 9 एस. सी. सी. 189 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बेगुनाही की धारणा को मानवाधिकार माना है। हालांकि अपवाद वैधानिक प्रावधानों द्वारा बनाया जा सकता है। लेकिन किसी विशेष कानून के तहत अभियुक्त के अपराध के ऐसे वैधानिक अनुमान को भी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में निहित तर्कसंगतता और स्वतंत्रता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।

19. नवीन धनीराम बरई बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2018 एससीसी ऑनलाइन बॉम 1281 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना है कि POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 29 के तहत अनुमान अभियुक्त के खिलाफ तभी लागू होता है जब अभियोजन पक्ष अधिनियम के तहत आरोप के संदर्भ में उसके खिलाफ उचित संदेह से परे मूलभूत तथ्यों को साबित कर देता है और अभियुक्त को अनुमान का खंडन करने का अधिकार है, या तो जिरह के माध्यम से अभियोजन पक्ष के गवाहों को बदनाम करके या अपने बचाव को साबित करने के लिए सबूत पेश करके। अनुमान का खंडन संभावना की प्रबलता की कसौटी पर होगा।

20. इसी तरह का विचार अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा भी व्यक्त किया गया है। यहाँ, कोई निम्नलिखित न्यायिक उदाहरणों का उल्लेख कर सकता है:-

(i) जॉय बनाम केरल राज्य, (2019) एससीसी ऑनलाइन केर 783

(ii) शाहिद हुसैन विश्वास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 5023

(iii) धर्मेन्द्र सिंह बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली सरकार) (2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 1267)

(iv) लाटू दास बनाम असम राज्य, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन गौ 5947

21. अब, हमें यह देखने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या अभियोजन पक्ष ने सूचना देने वाले/पीड़ित की अल्पमत और कथित अपराध के मूलभूत तथ्यों को साबित किया है।

अभियोजन साक्ष्य

22. अभिलेख पर साक्ष्य पर आते हुए, हम पाते हैं कि पीड़ित की जाँच पी.डब्ल्यू-5 के रूप में की गई है। उसने अपने जाँच-इन-चीफ में गवाही देकर अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है कि घटना 04.05.2014 पर रात में 12:00 बजे हुई थी। उसके चाचा महमूद साबरी, जो यहाँ अपीलकर्ता हैं, उसके घर आए और उसकी माँ को बताया कि उसकी बेटी गर्भवती है और उससे अनुरोध किया कि वह उसे (पीड़ित) अपनी बेटी की देखभाल के लिए भेजे। अपनी माँ से पूछने पर, वह अपीलार्थी के साथ बनारस चली गई। वह बनारस के एक लॉज में रहती थीं। उसने अपीलार्थी से उसे अपनी बेटी के पास ले जाने के लिए कहा, लेकिन अपीलार्थी ने कहा कि धोखे से एक लड़की को फोन करना उसका काम था और उसकी बेटी का उससे कोई लेना-देना नहीं था। उसने उसे नशीला पदार्थ पिलाया। वह बेहोश हो गई। बेहोशी की अवधि के दौरान, अपीलार्थी द्वारा उसका बलात्कार किया गया था। जब उसे रात के 12 बजे होश आया, तो उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं मिला। वह दर्द महसूस कर रही थी। कमरा बंद था। उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की लेकिन उनका मुँह बंद हो गया। उसे दो रात तक कमरे में बंद कर दिया गया और नशे में धुत होने के बाद उसके साथ बलात्कार किया गया। जब उसने पड़ोसी को घटना के बारे में बताया, तो उसने अपीलार्थी से घटना के बारे में पूछताछ की। अपीलार्थी ने उसकी पिटाई की और उसे रिक्शा से स्टेशन ले गया और रास्ते में उसे एक पुल से लटका दिया गया और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। उसने उसे तभी बचाया जब उसने उसे आश्वासन दिया कि वह इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएगी। फिर उसे ट्रेन से डेहरी-ऑन-सोन ले जाया गया और टेम्पो द्वारा अपीलार्थी के साथ तिलौथू लाया गया। तिलौथू में भी, अपीलार्थी ने उसे जंगल में अपने साथ जाने के लिए कहा, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया और अपीलार्थी के हाथ पर दाँत काटने के बाद वह भाग गई। रास्ते में वह बेहोश हो गई। एक आदमी उसे उसके घर ले गया। उसने अपनी दादी को घटना के बारे में बताया। उन्होंने धारा 164 सीआरपीसी के तहत भी अपना बयान दिया है।

23. अपनी जिरह में, उसने बयान दिया है कि अपीलकर्ता उसका चाचा (चचेरा चाचा) है जो 60-70 वर्ष का है और उसके बच्चे हैं। उनके आठ बेटे और दो बेटियां हैं। सात बेटे पहले से ही शादीशुदा हैं। वह रात 8 बजे बनारस पहुंची थी। वह लॉज का नाम नहीं बता सकी। उन्होंने बताया कि अपीलार्थी की बेटी बनारस में है। उसे दवा के नाम पर नशा दिया गया था। बलात्कार तब किया गया था जब वह बेहोश थी। होश में रहते हुए उसका बलात्कार नहीं किया गया था। होश में आने पर उसे संदेह हुआ कि उसके साथ कुछ गलत किया गया है। जब उसे अपने शरीर पर कपड़े नहीं मिले, तो उसने अपीलार्थी से पूछताछ की। वह उस व्यक्ति का नाम नहीं जानती है जिससे उसने बनारस के लॉज में शिकायत की थी। भोजन लॉज में ही लाया जाता था। वह यह नहीं बता सकी कि पुल कहाँ स्थित था और उसे कहाँ लटका दिया गया था। हालाँकि, उन्होंने बयान दिया है कि यह सीमेंट से बना था। जब वह लॉज से बाहर आई तो वह बेहोशी की हालत में थी। यह स्थिति दो महीने तक बनी रही। होश में आने के बाद उसने अपनी दादी, मां, चाचा और पिता को घटना के बारे में बताया। उनकी तीन बहनें और एक भाई है। बहनें उनसे बड़ी हैं और वे अविवाहित हैं। उनके पिता चादरों के विक्रेता हैं। लॉज में शौचालय कमरे से 10 फीट की दूरी पर अलग से स्थित था। पानी की पाइप कमरे के बाहर थी। वह दो दिन तक लॉज में रही थी, लेकिन वह पानी लेने के लिए कमरे से बाहर नहीं गई थी। वह शौचालय भी नहीं जा सकी क्योंकि वह बेहोश थी। दो दिन बाद वह अपने घर पहुंची और होश में आ गई। दर्द और खून बहने के कारण वह चलने में असमर्थ थी। यहां तक कि उसके बाएं स्तन पर काटने के संकेत भी थे। उसके पेट और पीठ पर 4-5 खरोंच भी थी। वह अविवाहित है। महमूद का बेटा अविवाहित है। उसके परिवार और अपीलार्थी के बीच विवाह होता है। अपीलार्थी के बेटे के साथ उसकी शादी के बारे में कोई बातचीत नहीं चल रही थी। वह पांचवीं कक्षा में पढ़ती है। उसने इस सुझाव का खंडन किया है कि उसके परिवार के सदस्य चाहते थे कि वह अपीलार्थी के बेटे के साथ शादी करे जिसके लिए अपीलार्थी तैयार नहीं था और यही कारण है कि अपीलार्थी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

24. पी.डब्ल्यू-1 पीड़ित की माँ है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट के अनुरूप अपने मुख्य परीक्षण में गवाही देकर अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। अपनी जिरह में, उसने गवाही दी है कि उसने घटना को नहीं देखा था, लेकिन उसने घटना के बारे में अपनी बेटी के बयान के अनुसार गवाही दी है।

25. पी.डब्ल्यू-2 पीड़ित की दादी है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट के अनुरूप अपने मुख्य परीक्षण में गवाही देकर अभियोजन पक्ष के मामले का भी समर्थन किया है। अपने मुख्य परीक्षण में, उसने गवाही दी है कि जब वह अपने घर वापस आई तो उसने पीड़ित के सलवार के सामने वाले हिस्से में खून और उसके व्यक्ति पर घर्षण और सूजन देखी थी।

26. पी.डब्ल्यू-3 मुखबिर है जो पीड़ित का चाचा होता है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट के अनुरूप अपने मुख्य परीक्षण में गवाही देते हुए अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। अपने जाँच-प्रभारी में, उन्होंने घटना के बारे में बयान दिया है। उसे पहली बार पीड़िता की माँ ने सूचित किया था। उसने पीड़ित के स्तन और गाल पर चोट और घर्षण भी देखा था। पीड़ित को पुलिस ने इलाज के लिए तिलौथू अस्पताल भेज दिया।

27. पी.डब्ल्यू-4 पीड़ित का पिता है। उसने लिखित रिपोर्ट के अनुरूप उसकी मुख्य परीक्षण के समक्ष गवाही देकर अभियोजन पक्ष के मामले का भी समर्थन किया है। उन्होंने आगे कहा कि जब उनकी बेटी दो दिन बाद उनके घर आई तो वह बेहोश होने के बाद नीचे गिर गई। उसे अपनी बेटी/पीड़ित से भी घटना के बारे में पता था। अपीलार्थी उसका चचेरा भाई है जिसकी आयु 60 वर्ष है। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि वह अपनी बेटी की शादी अपीलार्थी के बेटे से कराना चाहते थे, और उनके इनकार पर, उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

28. पी.डब्ल्यू-6 डॉ. रिचा चौधरी हैं, जिन्होंने 07.05.2014 को पीड़िता की मेडिको लीगल जांच की थी और उन्होंने अपनी जांच में निम्नलिखित पाया।

“अक्षीय और जघन बाल काले रंग में मौजूद होते हैं। स्तन रैखिक अवस्था-॥ तक विकसित हुआ। निजी भाग पर कोई असामान्य दाग या बाहरी कण नहीं होते हैं। बाएँ स्तन पर 3x1 सेमी घर्षण होता है। हाइमेन फट गया और 2 उंगलियों को प्रवेश दिया। वजाइनल स्वाब लिया गया और पैथोलॉजिकल जांच भेजी गई। मूत्र को गर्भावस्था परीक्षण के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट प्राप्त और संलग्न की गई। आयु निर्धारण डॉ. एस. बी. सिंह, डॉ. बी. के. पुष्कर और बी. के. सिंह द्वारा मेडिकल बोर्ड

द्वारा किया गया।
.....

दानिक और पैथोलॉजिकल परीक्षा के आधार पर-बाएं स्तन पर कोई महत्वपूर्ण सटीक घर्षण नहीं निकला। हालाँकि यह कहना मुश्किल है कि बलात्कार किया गया है या नहीं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मेडिकल बोर्ड ने उसकी उम्र का आकलन 12 से 14 वर्ष के बीच किया। ”

29. अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने बयान दिया है कि उसने पीड़ित व्यक्ति पर पाए गए घर्षण के रंग और समय के बारे में उल्लेख नहीं किया है। इस तरह का घर्षण एक तरफ सोने से नहीं हो सकता है।

30. पी.डब्लू-7 डॉ. पीयूष कुमार पुष्कर हैं। इसके अनुसार गवाह, उसने पीड़ित की उम्र निर्धारित करने के लिए मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में उसकी जांच की थी। परीक्षण के अनुसार, वह 12-14 वर्ष की पाई गई।

31. पी.डब्लू-8 अभिनंदन कुमार सिंह हैं, जो मामले के दूसरे आई. ओ. ने पहले आई. ओ. धीरेंद्र यादव से जांच की जिम्मेदारी ली थी। अपने प्रमुख जाँच में, उन्होंने बयान दिया है कि वाराणसी में घटना का स्थान कमरा नं0 46 अंजुमन मुस्लिम मुसाफिर खाना काजीपुरा कलां (दालमंडी), वाराणसी, हाउस नं. डी-50/229,230, वार्ड संख्या 61, पी. एस.-दशाश्वमेध, जिला - वाराणसी। उन्होंने उक्त मुसाफिर खाना के पास रखे रजिस्टर का भी निरीक्षण किया था। पता चला कि अपीलार्थी ने उक्त मुसाफिर खाना में कमरा संख्या 46 बुक किया था और पीड़ित के साथ 04.05.2014 पर वहाँ गया था और दिनांक 06.05.2014 लगभग 5.40 बजे चेक आउट किया था। यह कमरा उक्त मुसाफिर खान की पहली मंजिल पर स्थित था।

32. पी.डब्लू-9 डॉ. विजय कुमार सिंह हैं वो भी संबंधित समय में सदर अस्पताल, सासाराम में तैनात थे और वे पीड़ित की उम्र निर्धारित करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड के सदस्य थे। उन्होंने बयान दिया है कि परीक्षण रिपोर्ट डॉ. पीयूष कुमार पुष्कर (पी.डब्लू-7) द्वारा तैयार की गई थी और उन्होंने परीक्षण रिपोर्ट पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

33. पी.डब्लू-10 धीरेंद्र यादव, एस. आई. जो मामले के पहले जाँच अधिकारी थे। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि पीड़िता की चिकित्सकीय जांच की गई थी और धारा 164 सीआरपीसी के तहत उसका बयान भी दर्ज किया गया था। उसे पीड़ित के शरीर पर खरोंच मिली थी, लेकिन उसने डायरी में इसका

उल्लेख नहीं किया है। उसने यह भी कहा है कि पीड़ित ने उससे यह नहीं कहा था कि अपीलार्थी ने उससे कहा था कि किसी लड़की को धोखे से बुलाना अपीलार्थी का काम है।

बचाव साक्ष्य

34. बचाव पक्ष के तीन गवाहों से पूछताछ की गई है। D.W.-1 शाहबुबन बीबी अपीलार्थी की पत्नी हैं, जबकि डी. डब्ल्यू.-2 नजरून खातून है और D.W.-3 अपीलार्थी की सह-ग्रामीण सैबुन निशा है। उन सभी ने बयान दिया है कि पीड़ित के माता-पिता अपनी बेटी की शादी अपीलार्थी के बेटे से करना चाहते थे, जिसके लिए अपीलार्थी तैयार नहीं था और इसलिए उसे गलत तरीके से फंसाया गया है।

क्या सूचना देने वाला/पीड़ित घटना की तारीख को बच्चा था।

35. पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि कथित पीड़ित पॉक्सो अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के संदर्भ में घटना की तारीख को 18 साल से कम उम्र का बच्चा था। अपीलार्थी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के आवेदन के लिए यह एक पूर्व शर्त है।

36. अब सवाल यह है कि कथित पीड़ित की उम्र निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है? पॉक्सो अधिनियम में, पॉक्सो अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत ऐसी कोई प्रक्रिया प्रदान नहीं की गई है, केवल यह प्रावधान है कि यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो ऐसे प्रश्न का निर्धारण विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति की उम्र के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद किया जाना आवश्यक है और इस तरह के निर्धारण के लिए अपना कारण लिखित रूप में दर्ज करना आवश्यक है।

37. हालाँकि जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 7 एससीसी 263 के ऐतिहासिक फैसले में, जो अभी भी मान्य है और सभी न्यायालयों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोर की आयु के निर्धारण के लिए प्रदान की गई प्रक्रिया को अपराध के पीड़ित की आयु के निर्धारण के लिए भी अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक अल्पसंख्यक के मुद्दे का सवाल है, कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे और अपराध के शिकार बच्चे के बीच शायद ही कोई अंतर है।

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पी. युवाप्रकाश बनाम राज्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 846 के मामले में पोक्सो अधिनियम की धारा 34 और जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 94 का हवाला देते हुए इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है।

39. जे. जे. अधिनियम, 2015 की धारा 94, जो आयु के अनुमान और निर्धारण से संबंधित है, निम्नानुसार है:

“94. आयु का अनुमान और निर्धारण। -

(1) जहां समिति या बोर्ड को इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत (साक्ष्य देने के उद्देश्य के अलावा) उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की उपस्थिति के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, समिति या बोर्ड बच्चे की उम्र को लगभग बताते हुए ऐसी टिप्पणी दर्ज करेगा और उम्र की आगे की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना धारा 14 या धारा 36 के तहत जांच के साथ आगे बढ़ेगा।

(2) यदि समिति या बोर्ड के पास इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार है कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, साक्ष्य प्राप्त करके आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा-

(i) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;

(ii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र; पटना उच्च न्यायालय सी. आर.।

(iii) और केवल (i) और (ii) से ऊपर की अनुपस्थिति में, आयु का निर्धारण समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित एक अस्थिरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा: बशर्ते कि समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित ऐसी आयु निर्धारण परीक्षा ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा इस प्रकार उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु के रूप में अभिलिखित आयु, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी। ”

40. पी. युवाप्रकाश मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (ऊपर),

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया है:

“13. उपरोक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित होने के संदर्भ में किसी व्यक्ति की उम्र के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर अदालतों को जेजे अधिनियम की धारा 94 में बताए गए कदमों का सहारा लेना पड़ता है। किशोर न्याय अधिनियम में जिन तीन दस्तावेजों पर विचार करने की आवश्यकता है, वे यह हैं कि संबंधित न्यायालय को निम्नलिखित दस्तावेजों पर विचार करके आयु निर्धारित करनी होगी:

“(i) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;

(ii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र।

(iii) और केवल (i) और (ii) से ऊपर की अनुपस्थिति में, आयु का निर्धारण समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित एक अस्थिरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा।

(जोर दिया गया)

41. इस प्रकार, पीड़ित की आयु स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो, के आधार पर निर्धारित की जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि पीड़ित स्कूल का छात्र था, तो आयु के संबंध में प्रमाण के अन्य तरीकों पर वरीयता उपरोक्त प्रमाणपत्रों में है। इस तरह के प्रमाण पत्र के अभाव में, पीड़ित की उम्र के निर्धारण के लिए नगर निगम अधिकारियों या पंचायत द्वारा दिए गए जन्म प्रमाण पत्र पर विचार करना आवश्यक है। उपरोक्त प्रमाणपत्रों के अभाव में, पीड़ित की आयु को अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है। मौखिक साक्ष्य जैसे किसी भी अन्य प्रमाण को पीड़ित की उम्र के निर्धारण के लिए विचार से बाहर रखा गया है।

42. अब, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर आते हुए, हम पाते हैं कि दस अभियोजन पक्ष के गवाहों में से, पाँच गवाह (पी.डब्लू-1 से पी.डब्लू-5) गैर-आधिकारिक गवाह हैं, जिनमें से एक खुद पीड़ित है और बाकी उसकी माँ, पिता, चाचा और दादी हैं। पी.डब्लू-6, पी.डब्लू-7 और पी.डब्लू-8 डॉक्टर हैं। पी.डब्लू-6 ने पीड़ित की चिकित्सकीय कानूनी जांच की थी जबकि पी.डब्लू-7 और पी.डब्लू-9 मेडिकल बोर्ड के सदस्य हैं जो पीड़ित की उम्र के निर्धारण के लिए गठित किया गया था और उनके साक्ष्य के अनुसार, पीड़ित को रेडियोलॉजिकल परीक्षण के आधार पर 12-14 वर्ष का पाया गया था। पी.डब्लू-8 और पी.डब्लू-10 मामले के जाँच अधिकारी थे।

43. हम आगे पाते हैं कि पीड़ित पांचवीं कक्षा का एक स्कूली छात्र था, लेकिन कोई भी स्कूल प्रमाण पत्र या पंचायत या नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाया गया है। हालाँकि, चिकित्सा परीक्षण के अनुसार, पीड़ित की आयु 12-14 वर्ष पाई गई है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के अनुसार, स्कूल प्रमाण पत्र या पंचायत या नगरपालिका प्राधिकरण से किसी भी प्रमाण पत्र के अभाव में, पीड़ित की आयु को अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

44. इस प्रकार, हम पाते हैं कि पीड़ित की उम्र के संबंध में केवल चिकित्सा राय है।

45. हालांकि, यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि किसी व्यक्ति की उम्र के बारे में चिकित्सा राय निर्णायक साक्ष्य नहीं है, क्योंकि आयु का सटीक मूल्यांकन चिकित्सा परीक्षण के आधार पर नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमेशा उच्च और निम्न दोनों पक्षों में त्रुटियों की संभावना होती है। हालांकि, जे. जे. अधिनियम, 2015 की धारा 94 (2) में उल्लिखित दस्तावेजों की अनुपस्थिति में चिकित्सा राय बहुत उपयोगी मार्गदर्शक कारक हो सकते हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। रिलायंस को निम्नलिखित प्राधिकरणों पर रखा गया है:

- (i) ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 8 एस. सी. सी. 602
- (ii) मुकर्रब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2017) 2 एस. सी. सी. 210;
- (iii) एम. पी. राज्य बनाम अनूप सिंह (2015) 7 एस. सी. सी. 773
- (iv) अबुजर हुसैन बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य, (2012) 10 एस. सी. सी. 489;

46. यहां, मुकर्रब केस (सुप्रा) का संदर्भ देना प्रासंगिक होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा राय के साक्ष्य मूल्य के संबंध में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

“26. इस मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, किसी व्यक्ति की उम्र के बारे में एक अंधे और यांत्रिक दृष्टिकोण को केवल रेडियोलॉजिकल परीक्षा द्वारा चिकित्सा राय के आधार पर नहीं अपनाया जा सकता है। मोदी की मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस की पाठ्यपुस्तक के पी 31 और टॉक्सिकोलॉजी, 20 वीं संस्करण, इसे इस प्रकार कहा गया है:

“शरीर के दोनों ओर के ऊपरी या निचले छोर के किसी भी मुख्य जोड़ के युवा व्यक्ति के रेडियोग्राम की आयु का पता लगाने के लिए, निम्नलिखित तालिका के अनुसार एक राय दी जानी चाहिए, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि इस तालिका पर बहुत अधिक निर्भरता नहीं रखी जानी चाहिए क्योंकि यह केवल एक औसत का संकेत देता है और विकास की विलक्षणताओं के कारण एक ही प्रांत के व्यक्तिगत मामलों में भी भिन्न होने की संभावना है। ”

अदालतों ने इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया है और हमेशा यह माना है कि रेडियोलॉजिकल परीक्षा द्वारा प्रदान किया गया साक्ष्य निस्संदेह किसी व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक कारक है, लेकिन साक्ष्य निर्णायक और निर्विवाद प्रकृति का नहीं है और यह त्रुटि के अंतर के अधीन है। एक व्यक्ति की उम्र के रूप में चिकित्सा साक्ष्य हालांकि एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक निर्णायक नहीं है और अन्य परिस्थितियों के साथ विचार किया जाना चाहिए।

27. हाल के एक फैसले में, एम. पी. बनाम राज्य अनूप सिंह, (2015) 7 एस. सी. सी. 773, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अस्थिकरण परीक्षण आयु निर्धारण के लिए एकमात्र मानदंड नहीं है। बबलू पासी बनाम झारखंड राज्य, (2008) 13 एस. सी. सी. 133 और एम. पी. राज्य बनाम अनूप सिंह, (2015) 7 एस. सी. सी. 773, हम मानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की आयु का पता लगाने की बात आती है तो अस्थिकरण परीक्षण को निर्णायक नहीं माना जा सकता है। इसके

अलावा, इसमें अपीलकर्ताओं ने निश्चित रूप से तीस वर्ष की आयु को पार कर लिया है, जो एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि आयु का निर्धारण सटीकता के साथ नहीं किया जा सकता है। वास्तव में अपीलार्थियों की चिकित्सा रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दंत एक्स-रे के लिए कोई संकेत नहीं था क्योंकि दोनों अभियुक्तों की आयु 25 वर्ष से अधिक थी।

28. इस मोड़ पर, हम उपयोगी रूप से एक लेख "मध्य राजस्थान में बाल चिकित्सा समूह में आयु अनुमान के लिए कलाई ऑसिफिकेशन का एक अध्ययन" का उल्लेख कर सकते हैं, जो नीचे दिया गया है:

"एक व्यक्ति की आयु के निर्धारण के लिए विभिन्न मानदंड हैं। जिसमें से दांतों का फटना और हड्डियों की अस्थीकरण गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं। फिर भी आमतौर पर कम आयु वर्ग में एपिफिसल संलयन के साथ दंत चिकित्सा और अस्थीकरण द्वारा उम्र का अधिक सटीक आकलन किया जा सकता है।

[संदर्भ:ग्रे एच. ग्रे की शरीर रचना विज्ञान, 37 वीं संस्करण। चर्चिल लिविंगस्टोन एडिनबर्ग लंदन मेलबर्न और न्यूयॉर्क:1996; 341-342];

दांतों की सावधानीपूर्वक जांच और कलाई के जोड़ में ऑसिफिकेशन बच्चों में उम्र के आकलन के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान करता है।

[संदर्भ:पारिख सी. के. पारिख की मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी की पाठ्यपुस्तक, 5 वीं संस्करण।

मुंबई मेडिको-लीगल सेंटर कोलाबा:1990; 44-45]; ***

कलाई के जोड़ में अस्थीकरण के केंद्र की उपस्थिति में भिन्नता नस्ल, जलवायु, आहार और क्षेत्रीय कारकों के प्रभाव को दर्शाती है। त्रिज्या और अल्ना के दूरस्थ छोरों के लिए वर्तमान अध्ययन के अनुरूप ऑसिफिकेशन केंद्र डॉ. आशुतोष का लेख "मध्य राजस्थान में बाल चिकित्सा समूह में आयु के आकलन के लिए कलाई के अस्थीकरण का एक अध्ययन" श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रदर्शनकारी और अन्य डॉक्टरों की एक टीम, जर्नल ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन (जे. आई. ए. एफ. एम.), 2004; 26 (4)। आईएसएसएन 0971-0973]। "

47. इसलिए, उपस्थित परिस्थितियों के साथ-साथ चिकित्सा राय पर भी हमेशा विचार किया जाना चाहिए। अभिलेख पर साक्ष्य के अनुसार, केवल उपस्थित परिस्थिति ही पीड़ित के पिता की मौखिक गवाही है जिसने अपने प्रमुख परीक्षण में बयान दिया है कि कथित घटना के समय पीड़ित की आयु 12 वर्ष थी। हालांकि, कानूनी आवश्यकता के बावजूद, उन्होंने पीड़ित की उम्र के संबंध में कोई स्कूल प्रमाण पत्र या पंचायत या नगर निगम प्राधिकरण प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर नहीं लाया है। इस प्रकार, पीड़ित के पिता की मौखिक गवाही और चिकित्सा राय को देखते हुए, कथित तारीख को पीड़ित की आयु 12 वर्ष से अधिक पाई जाती है। घटना। इसलिए, पीड़ित एक बच्चा था और अपीलार्थी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।

क्या अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ उचित संदेह से परे कथित अपराध के मूलभूत तथ्यों को साबित किया है।

48. तथापि, इससे पहले कि हम इस संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य पर चर्चा करें और उसकी सराहना करें, पक्षों की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य की सराहना के कुछ सिद्धांतों का उल्लेख करना उचित होगा।

49. यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि अभियोजन को केवल इस आधार पर खारिज या संदेह नहीं किया जा सकता है कि स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है क्योंकि अनुभव के अनुसार, सभ्य लोग आम तौर पर असंवेदनशील होते हैं जब उनकी उपस्थिति में कोई अपराध किया जाता है। वे पीड़ित और चौकीदार दोनों से अलग हो जाते हैं। वे खुद को अदालत से दूर रखते हैं जब तक कि यह अपरिहार्य न हो। इसलिए न्यायालय को स्वतंत्र गवाहों की कमी के कारण अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह करने के बजाय अपनी योग्यता के आधार पर संबंधित गवाहों के साक्ष्य की भी सराहना करने की आवश्यकता है। [अप्पाभाई और एक अन्य बनाम गुजरात राज्य, 1988 पूरक एस. सी. सी. 241 का संदर्भ लें।]

50. यह भी कानून की एक स्थिर स्थिति है कि किसी भी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य के साक्ष्य को केवल मृतक के साथ उसके संबंध के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसे गवाहों के साक्ष्य को सच्चाई की कसौटी पर तौलना पड़ता है और अधिक से अधिक अदालत को उनके साक्ष्य की सराहना करते समय सावधानी और सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में, कोई निम्नलिखित न्यायिक उदाहरणों का उल्लेख कर सकता है:

- (i) अभिषेक शर्मा बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र),
2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1358;
- (ii) योगीश सिंह बनाम महाबीर सिंह और अन्य।
(2017) 11 एस. सी. सी. 195;
- (ग) गुजरात राज्य, 1988 पूरक एस. सी. सी. 241
(2012) 4 एससीसी 79;
- (iv) दौलतराम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य,
2009 (1) जे. आई. जे 1;
- (v) राज्य बनाम सरवनन,
(ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 152);
- (vi) यू. पी. राज्य बनाम किशनपाल,
(2008) 16 एससीसी 73;
- (vii) नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य,
(2007) 14 एससीसी 150;

- (viii) ए. पी. राज्य बनाम एस. रायप्पा,
(2006) 4 एस. सी. सी. 512;
- (ix) पुलिचेरला नागराजू बनाम ए. पी. राज्य।,
(2006) 11 एससीसी 444;
- (x) हरबंस कौर बनाम हरियाणा राज्य;
(2005) 9 एस. सी. सी. 195;
- (xi) हरि ओबुला रेड्डी और अन्य बनाम एपी राज्य,
(1981) 3 एस. सी. सी. 675
- (xii) प्यारा सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य,
(1977) 4 एससीसी 452

51. यह भी कानून की एक स्थिर स्थिति है कि अभियोजन मामले की जड़ तक नहीं जाने वाले तुच्छ मामलों पर छोटी विसंगतियों, विरोधाभासों, सुधारों, अलंकरणों या चूक को अनुचित महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि वे अभियोजन पक्ष के मामले के भौतिक विवरणों से संबंधित हैं, तो ऐसे गवाहों की गवाही को खारिज किया जा सकता है। इस संबंध में, कोई निम्नलिखित न्यायिक उदाहरणों का उल्लेख कर सकता है:

- (i) सी. मुनियप्पन और अन्य बनाम टी. एन. राज्य,
(2010)9SCC567;
- (ii) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण मास्टर,
(ए. आई. आर 2010 एस. सी. 3071);
- (iii) अप्पाभाई और बनाम गुजरात राज्य,
ए. आई. आर 1988 एस. सी. 696;
- (iv) शिवाजी एस. बोबडे और अन्य बनाम राज्य
महाराष्ट्र (1973 ए. आई. आर. 2622);
- (v) संजय कुमार बनाम बिहार राज्य,
2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 1077;
- (vi) मध्य प्रदेश राज्य बनाम दल सिंह,
(2013) 14 एससीसी 159;
- (vii) श्रीमती. शमीम बनाम राज्य (दिल्ली का जीएनसीटी),
2018 (4) पीएलजेआर 160;
- (viii) एस. गोविंदारजू बनाम कर्नाटक राज्य,
2013 (10) स्केल 454
- (ix) नरोत्तम सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य।
(ए. आई. आर 1978 एस. सी. 1542)
- (x) लीला राम बनाम हरियाणा राज्य,
(1999) 9 एससीसी 525;
- (xi) सुबल घोराई और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य,
(2013) 4 एससीसी 607;
- (xii) योगेश सिंह बनाम महावीर सिंह और अन्य,

(2017) 11 एस. सी. सी. 195

52. अब अभिलेख पर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर आते हुए, हम पाते हैं कि पीड़ित (पी.डब्लू-5) केवल कथित घटना का चश्मदीद गवाह है और अन्य गैर-आधिकारिक गवाह (पी.डब्लू-1 से पी.डब्लू-4) केवल घटना से पहले और बाद के तथ्यों और परिस्थितियों के गवाह हैं। इस प्रकार, पी.डब्लू-5 अभियोजन पक्ष का प्रमुख गवाह है। यह भी कानून की स्थिति है कि अभियोजक की एकमात्र गवाही के आधार पर, आरोपी को उसकी गवाही की पुष्टि किए बिना दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह एक सहयोगी नहीं है और वह एक घायल गवाह के आधार पर खड़ी है। इस तरह की दोषसिद्धि के लिए, केवल आवश्यकता यह है कि अभियोजक को न्यायालय का विश्वसनीय, प्रेरक विश्वास होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वह एक उत्कृष्ट गवाह होनी चाहिए।

53. अभिलेख पर उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से, हम पाते हैं कि अभियोजक की गवाही (पी.डब्लू-5) सुसंगत और सच्ची है। अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ तक जाने वाले उनके बयानों में कोई बड़ा विरोधाभास नहीं है। मामूली मामलों पर कुछ छोटी-मोटी विसंगतियाँ यहाँ-वहाँ पाई जा सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर, उसकी गवाही सच्ची और विश्वसनीय है।

54. अभियोजक की गवाही भी चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित है, जिसके अनुसार पीड़ित का हाइमेन टूटा हुआ पाया गया था और पी.डब्लू-6 जिसने उसकी जांच की है, उसने राय दी है कि बलात्कार के होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अन्य गवाहों के साक्ष्य से यह साबित होता है कि अपीलार्थी पीड़ित को बनारस ले गया था और वह उसके साथ दो दिनों तक एक लॉज में रहा। यहां तक कि आई. ओ. ने भी लॉज के रजिस्टर को सत्यापित किया था और पाया था कि अपीलार्थी पीड़ित के साथ एक कमरे में रहा था। हम सूचना देने वाले द्वारा अपीलार्थी के गलत निहितार्थ का कोई कारण भी नहीं पाते हैं। अपीलार्थी और अभियोजक के परिवार के बीच कोई पिछली दुश्मनी नहीं है, हालांकि बचाव पक्ष के गवाहों ने बयान दिया है कि पीड़ित के माता-पिता अपीलार्थी के बेटे के साथ उसकी शादी कराना चाहते थे और जब अपीलार्थी ने अपने बेटे की शादी करने से इनकार कर दिया, तो उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। लेकिन अभिलेख पर

साक्ष्य की समग्रता को देखते हुए, हम पाते हैं कि इस तरह की बचाव याचिका प्रेरक नहीं है। यदि बचाव पक्ष की याचिका सही होती तो अपीलार्थी के बेटे को भी मामले में फंसाया जा सकता था। लेकिन वह इस मामले में आरोपी नहीं है। इसके अलावा, पीड़ित की दो बड़ी बहनें हैं जो अभी भी अविवाहित हैं और सामाजिक प्रथा के अनुसार, यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि माता-पिता तीसरी बेटी की शादी की पेशकश करेंगे जब उनकी दो बड़ी बेटियां अभी भी अविवाहित होंगी। इसके अलावा, हम पाते हैं कि बचाव पक्ष के साक्ष्य में, तारीख और स्थान के संदर्भ में, पीड़ित के माता-पिता की ओर से शादी के प्रस्ताव का कोई विवरण नहीं है। इसलिए, बचाव पक्ष में यह कहने में कोई सार नहीं है कि अपीलार्थी को पीड़ित के साथ अपने बेटे की शादी कराने से इनकार करने पर झूठा फंसाया गया है। इसके अलावा, अपीलार्थी द्वारा पीड़ित को बनारस ले जाने और उसके साथ दो दिनों तक एक लॉज में रहने के बारे में ठोस साक्ष्य को देखते हुए अभियोजक की गवाही की पुष्टि होती है।

55. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष ने कथित अपराध के मूलभूत तथ्यों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है और पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और 30 के तहत धारणा अपीलार्थी के खिलाफ उठाई गई है। लेकिन अपीलार्थी अपने बचाव में सबूत पेश किए जाने के बावजूद इस धारणा का खंडन करने में सफल नहीं हुआ है।

56. इसलिए, हम मानते हैं कि अपीलार्थी पीड़ित के खिलाफ भेदक यौन उत्पीड़न करने का दोषी है।

57. हालाँकि, हम पाते हैं कि विद्वत विचारण न्यायालय ने दोषी/अपीलार्थी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत सजा सुनाकर और उसे शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाकर दंडित करने के लिए गलत वैधानिक प्रावधानों को लागू किया है। ज्ञात विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है कि कथित अपराध वर्ष 2014 में किया गया है और उस समय अधिनियम की धारा 6 में ऐसी कोई सजा नहीं थी। इसके अलावा, पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के प्रावधानों के अनुसार, हम पाते हैं कि वर्तमान मामला पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत आता है, न कि पॉक्सो अधिनियम

की धारा 6 के तहत, क्योंकि पीड़िता की आयु 12 वर्ष से अधिक पाई गई है और इसलिए, उसके खिलाफ किया गया भेदक यौन हमला पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 के तहत परिभाषित उग्र भेदक यौन हमले के तहत नहीं आता है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, केवल 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर भेदक यौन हमला उग्र भेदक यौन हमले की श्रेणी में आता है। यदि पीड़ित बच्चा 12 वर्ष से अधिक आयु का है, तो यौन हमला पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है। इसके अलावा, पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, जो 2019 में संशोधन से पहले मौजूद थी, भेदक यौन हमले के लिए किसी भी अवधि के कारावास की सजा है जो 7 साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी। पीड़ित के खिलाफ किया गया भेदक यौन हमला भी आई. पी. सी. की धारा 376 (1) के तहत आता है जो 2019 में इसके संशोधन से पहले पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रदान की गई सजा का भी प्रावधान करता है।

58. हम आगे पाते हैं कि मामले के कुल तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से अपीलार्थी की वृद्धावस्था को देखते हुए, अपीलार्थी को 10 साल का कारावास न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा, जबकि अपीलार्थी पहले से ही 10 साल से अधिक समय से हिरासत में है। इसलिए, उन्हें पहले से ही हिरासत में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई जाती है।

59. हम आगे पाते हैं कि विद्वत ट्रायल कोर्ट ने सासाराम में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, रोहतास द्वारा पीड़ित को देय रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है। लेकिन पीड़ित की उम्र को देखते हुए, हम इस मुआवजे में रुपये की वृद्धि करना उचित समझते हैं। तदनुसार, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को रुपये की अतिरिक्त मुआवजे की राशि 1,00,000/- इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

60. हम यह भी पाते हैं कि विद्वत विचारण न्यायालय ने दोषी/अपीलार्थी पर Rs. 50,000/- का जुर्माना लगाया है। हम निर्देश देते हैं कि जुर्माने की यह राशि पीड़ित को देय होगी। अपीलार्थी द्वारा इस आदेश के दो महीने के भीतर

पीडित को जुर्माना देने में चूक के मामले में, अपीलार्थी एक वर्ष के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास से गुजरने के लिए उत्तरदायी होगा।

61. तदनुसार, अपील आंशिक रूप से स्वीकृत है।

62. अपीलार्थी को निर्देश दिया जाता है कि यदि उसकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।

63. इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन और अभिलेख के लिए तुरंत संबंधित जेल के अधीक्षक को भेजी जाए।

64. मुकदमे के अभिलेखों को तुरंत निचली अदालत को वापस कर दिया जाए।

65. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

मैं सहमत हूँ।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

चंदन/एस. अली/रविशंकर -

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।